स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा प्रणाली में किया जाएगा बदलाव

Dainik Jagran 18-07-2026

- मार्च 2027 से प्रत्येक प्रश्नपत्र में होंगे केस स्टडी आधारित प्रश्न
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत लागू होगी नई प्रणाली

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परख के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मार्च 2027 से बोर्ड परीक्षाओं के प्रत्येक प्रश्नपत्र में दो केस स्टडी आधारित प्रश्न अनिवार्य होंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की तार्किक सोच, विश्लेषण क्षमता व समस्या समाधान कौशल का आकलन करना है।

डा. राजेश शर्मा • जागरण

बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित होंगे। विद्यार्थियों को किसी स्थिति या घटना का विवरण दिया जाएगा, जिसका विश्लेषण कर उन्हें अपने विषय ज्ञान और तार्किक समझ के आधार पर उत्तर देना होगा। उन्होंने कहा कि केस स्टडी आधारित प्रश्न विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों से जोड़ेंगे और विषय की गहरी समझ विकसित करने में मदद करेंगे। यह बदलाव शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और विद्यार्थी केंद्रित बनाएगा। नई परीक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रश्नपत्र निर्माण प्रक्रिया में भी बदलाव किया जा रहा है।

यह प्रणाली विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए नई होगी। इसलिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बोर्ड समय-समय पर दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन भी करेगा ताकि स्कूल इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।

Divya Himachal 18-07-2026

छात्र अब रटने की आदत को कहें गुडबाय

बोर्ड परीक्षाओं में अब केस स्टडी आधारित सवालों से होगी छात्रों की तार्किक क्षमता की परख

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को धरातल पर उतारते हुए, बोर्ड ने फैसला लिया है कि मार्च 2027 से होने वाली परीक्षाओं में छात्रों को सिर्फ रटे-रटाए ज्ञान के आधार पर नहीं परखा जाएगा। इसके बजाय, उनके तार्किक चिंतन और विश्लेषणात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए प्रश्न-पत्रों में केस स्टडी आधारित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने इस अहम बदलाव की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब हर विषय के प्रश्न-पत्र में दो केस स्टडी आधारित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। इन सवालों में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या किसी विशेष संदर्भ का एक पूरा विवरण (सिचुएशन) दिया जाएगा। छात्रों को उस परिस्थिति का विश्लेषण कर अपने ज्ञान, समझ और तार्किक क्षमता के आधार पर सटीक उत्तर देने होंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र विषय को सिर्फ तथ्यों के रूप में याद न रखें, बल्कि उसे समझें और व्यावहारिक जीवन में लागू करना सीखें।

विकसित होगी निर्णय लेने की क्षमता

केस स्टडी वाले प्रश्न छात्रों को किताबी दुनिया से निकालकर वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ेंगे। इससे उनमें आलोचनात्मक चिंतन और किसी भी विषय को गहराई से समझने का दृष्टिकोण विकसित होगा।

- मार्च 2027 से हर प्रश्नपत्र में अनिवार्य होंगे दो केस स्टडी वाले सवाल

बदलाव यह बदलाव न केवल छात्रों को उच्च शिक्षा और कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत बनाएगा, बल्कि उन्हें असल जिंदगी की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए भी तैयार करेगा।

बदलेगा पेपर सेट करने का तरीका

इस बड़े बदलाव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शिक्षा बोर्ड ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रश्न-पत्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया को आधुनिक शैक्षिक मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जा रहा है।

केस स्टडी आधारित सवालों से होगी तार्किक क्षमता की परख

हिमाचल दस्तक ▪ धर्मशाला

▪ मार्च से हर प्रश्न-पत्र में अनिवार्य होंगे दो केस स्टडी वाले सवाल

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन को धरातल पर उतारते हुए, बोर्ड ने फैसला लिया है कि मार्च, 2027 से होने वाली परीक्षाओं में छात्रों को सिर्फ रटे-रटाए ज्ञान के आधार पर नहीं परखा जाएगा।

इसके बजाय, उनके तार्किक चिंतन और विश्लेषणात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए प्रश्न-पत्रों में केस स्टडी आधारित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस अहम बदलाव की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब हर विषय के प्रश्न-पत्र में दो केस स्टडी आधारित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। इन सवालों में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या किसी विशेष संदर्भ का एक पूरा विवरण दिया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र विषय को सिर्फ तथ्यों के रूप में याद न रखें, बल्कि उसे समझें और व्यावहारिक जीवन में लागू करना सीखें। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षा को केवल रटने की प्रवृत्ति से बाहर निकालकर समस्या-समाधान और निर्णय लेने की क्षमता तक ले जाना समय की सबसे बड़ी मांग है।

HP बोर्ड परीक्षाओं में अब केस स्टडी आधारित सवालों से होगी छात्रों की तार्किक क्षमता की परख

दैनिक जागो वर्ल्ड ! धर्मशाला/राकेश कुमार

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने राज्य की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के विजन को धरातल पर उतारते हुए, बोर्ड ने फैसला लिया है कि मार्च 2027 से होने वाली परीक्षाओं में छात्रों को सिर्फ रटे-रटाए ज्ञान के आधार पर नहीं परखा जाएगा। इसके बजाय, उनके तार्किक चिंतन और विश्लेषणात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए प्रश्न-पत्रों में 'केस स्टडी' (Case Study) आधारित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। **वास्तविक जीवन की चुनौतियों से जुड़े होंगे सवाल** हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस अहम बदलाव की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब हर विषय के प्रश्न-पत्र में दो केस स्टडी आधारित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। इन सवालों में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या किसी विशेष संदर्भ का एक पूरा विवरण (सिचुएशन) दिया जाएगा। छात्रों को उस परिस्थिति का विश्लेषण कर अपने ज्ञान, समझ और

तार्किक क्षमता के आधार पर सटीक उत्तर देने होंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र विषय को सिर्फ तथ्यों के रूप में याद न रखें, बल्कि उसे समझें और व्यावहारिक जीवन में लागू करना सीखें। रटने की प्रवृत्ति से मिलेगी मुक्ति, विकसित होगी निर्णय लेने की क्षमतावर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षा को केवल रटने की प्रवृत्ति से बाहर निकालकर समस्या-समाधान (Problem Solving) और निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) तक ले जाना समय की सबसे बड़ी मांग है। डॉ. शर्मा ने कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग है। केस स्टडी वाले प्रश्न छात्रों को किताबी दुनिया से निकालकर वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ेंगे। इससे उनमें आलोचनात्मक चिंतन (Critical Thinking) और किसी भी विषय को गहराई से समझने का दृष्टिकोण विकसित होगा।शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग, बदलेगा पेपर सेट करने का तरीकाइस बड़े बदलाव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शिक्षा बोर्ड ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रश्न-पत्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया को आधुनिक शैक्षिक मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जा रहा है। चूंकि यह परीक्षा प्रणाली छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए नई होगी, इसलिए स्कूलों और शिक्षकों को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। बोर्ड की ओर से समय-समय पर जरूरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को इस दक्षता-आधारित परीक्षा प्रणाली के लिए पूरी तरह तैयार कर सकें।हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड का यह कदम परीक्षा प्रणाली को अधिक विद्यार्थी-केंद्रित और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। यह बदलाव न केवल छात्रों को उच्च शिक्षा और कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत बनाएगा, बल्कि उन्हें असल जिंदगी की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए भी तैयार करेगा।

HP Board exams to test students' logical reasoning through case study-based questions

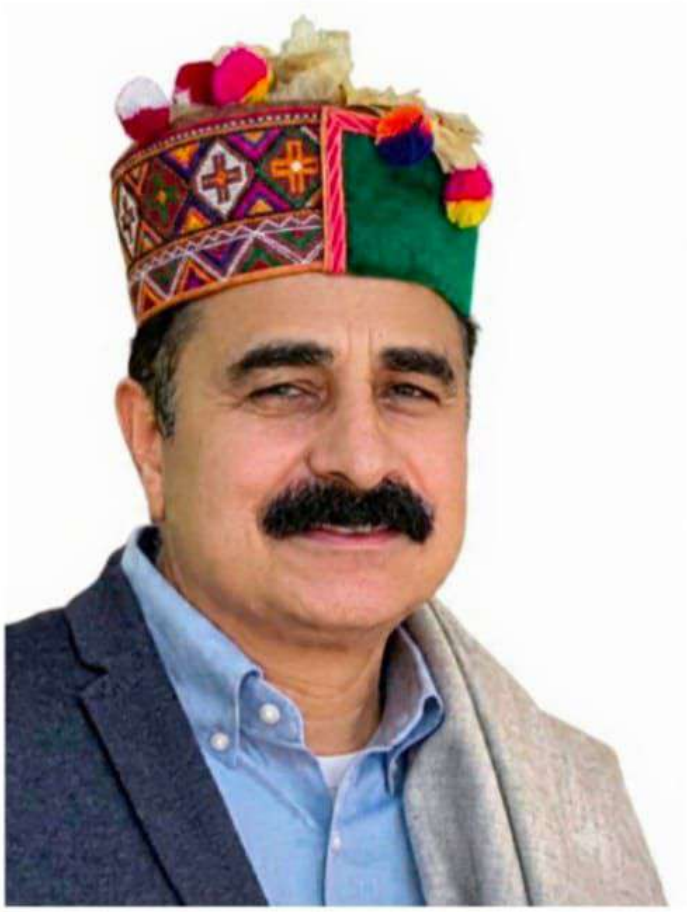

SANJAY AGGARWAL

DHARAMSHALA JUL 17 : The Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) has announced a major and historic shift in the state's education and examination system. Aligning with the vision of the National Education Policy (NEP-2020), the Board has decided that, starting with the March 2027 examinations, students will no longer be assessed solely on the basis of rote-learned knowledge. Instead, 'case study'-based questions will be included in question papers to evaluate their logical thinking and analytical capabilities. Dr. Rajesh Sharma, Chairman of the School Education Board, shared details regarding this significant change. He explained that under the new system, two case study-based questions will be mandatory in the question paper for every subject. These questions will present a detailed scenario based on real-life situations or specific contexts. Students will be required to analyze the situation and provide accurate answers based on their knowledge, understanding, and logical reasoning. The primary objective of this initiative is to ensure that students do not merely memorize facts but understand the subject matter and learn to apply it in practical life. In the current educational landscape, shifting the focus from rote learning to problem-solving and decision-making capabilities is the need of the hour. Dr. Sharma stated that the true purpose of education is the practical application of knowledge. Case study questions will connect students with real-life situations, moving them beyond the confines of textbooks.

डिजिटल अख़बार
पहली नज़र
सबसे पहले, सबसे तेज
पहली नज़र
आज की ताजा ख़बर देखते रहिए
डिजिटल न्यूज पेपर पहली नज़र के साथ
17 जुलाई, 2026 www.pehalinazar.com pehalinazarhp@gmail.com

रटने की आदत को 'गुडबाय'

एचपी बोर्ड परीक्षाओं में अब केस स्टडी आधारित सवालों से होगी छात्रों की तार्किक क्षमता की परख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और 'परख' के दिशा-निर्देशों पर अमल

मार्च 2027 से हर प्रश्न-पत्र में अनिवार्य होंगे दो केस स्टडी वाले सवाल

पहली नजर ब्यूरो, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के विजन को धरातल पर उतारते हुए, बोर्ड ने फैसला लिया है कि मार्च 2027 से होने वाली परीक्षाओं में छात्रों को सिर्फ रटे-रटाए ज्ञान के आधार पर नहीं परखा जाएगा। इसके बजाय, उनके तार्किक चिंतन और विश्लेषणात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए प्रश्न-पत्रों में 'केस स्टडी' (केस स्टडी) आधारित प्रश्नों को शामिल किया

जाएगा।

● वास्तविक जीवन की चुनौतियों से जुड़े होंगे सवाल

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस अहम बदलाव की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब हर विषय के प्रश्न-पत्र में दो केस स्टडी आधारित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। इन सवालों में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या किसी विशेष संदर्भ का एक पूरा विवरण (सिचुएशन) दिया जाएगा। छात्रों को उस परिस्थिति का विश्लेषण कर अपने ज्ञान, समझ और तार्किक क्षमता के आधार पर सटीक उत्तर देने होंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र विषय को सिर्फ तथ्यों के रूप में याद न रखें, बल्कि उसे समझें और व्यावहारिक जीवन में लागू करना सीखें।

● रटने की प्रवृत्ति से मिलेगी मुक्ति, विकसित होगी निर्णय लेने की क्षमता

वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षा को केवल रटने की प्रवृत्ति से बाहर निकालकर समस्या-समाधान (प्रॉब्लम सॉल्विंग) और निर्णय लेने की क्षमता (डिसीजन मेकिंग) तक ले जाना समय की सबसे बड़ी मांग है। डॉ. शर्मा ने कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग है। केस स्टडी वाले प्रश्न छात्रों को किताबी दुनिया से निकालकर वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ेंगे। इससे उनमें आलोचनात्मक चिंतन (क्रिटिकल थिंकिंग) और किसी भी विषय को गहराई से समझने का दृष्टिकोण विकसित होगा।

शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग, बदलेगा पेपर सेट करने का तरीका

इस बड़े बदलाव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शिक्षा बोर्ड ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रश्न-पत्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया को आधुनिक शैक्षिक मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जा रहा है। चूंकि यह परीक्षा प्रणाली छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए नई होगी, इसलिए स्कूलों और शिक्षकों को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। बोर्ड की ओर से समय-समय पर जरूरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को इस दक्षता-आधारित परीक्षा प्रणाली के लिए पूरी तरह तैयार कर सकें।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत बनाएगा बदलाव

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड का यह कदम परीक्षा प्रणाली को अधिक विद्यार्थी-केंद्रित और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। यह बदलाव न केवल छात्रों को उच्च शिक्षा और कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत बनाएगा, बल्कि उन्हें असल जिंदगी की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए भी तैयार करेगा।

JULY 18, 2026 SATURDAY DHARAMSHALA

The Sunny Times

HIMACHAL BOARD QUESTIONS WILL NOW REQUIRE STUDENTS TO THINK, NOT JUST CRAM

Sunny Mahajan | Dharamshala

Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) has finally decided to check if kids can actually think. Starting March 2027, the board is making a historic, high-stakes pivot toward sanity by making case study-based questions mandatory in all exam papers.

Aligned with the National Education Policy (NEP-2020) and the central monitoring body 'PARKH' guidelines, this reform means the days of mindlessly vomiting memorized textbook pages onto an answer sheet are officially numbered. Instead, students will face real-world scenarios designed to test their logic, analytical skills, and critical thinking.

HPBOSE Chairman Dr. Rajesh Sharma confirmed that every single question paper will feature exactly two case-study problems. These won't be your standard "define this concept" prompts. Instead, students will be handed complex, real-life situations and asked to solve them using actual understanding rather than blind memory.

It turns out education is supposed to prepare you for life, not just for passing exams. The board wants to build problem-solvers and decision-makers, which is a bold ask for a system that has historically worshipped cramming.

Of course, you can't just change the rules of the game without telling the players. Because this new analytical universe is going to shock both students and teachers, HPBOSE is gearing up to modernize its entire paper-setting process. The board is rolling out specialized training sessions for teachers to upgrade their skills, ensuring they don't teach the old way while trying to test the new way. While the sudden demand for critical thinking might trigger some initial panic in classrooms across the state, this futuristic leap promises to make Himachal's students sharp enough to handle both competitive exams and the unpredictable chaos of the real world.